ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज अस्पताल.....

पेज एक का शेष

दिया गया है जिनके पैसे से यह बनाया वे चलाया जा रहा है। यहां की ओपीडी यानी दैनिक आने वाले मरीजों की संख्या 4000 थी जिन्हें एक झटके में बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। दरअसल आज ट्रेड यूनियन आंदोलन खुद मरा पड़ा है इसलिये ईएसआई कवर्ड मजदूरों के साथ यह अन्याय हो रहा है।

हरियाणा सरकार का अपना बीके अस्पताल जिसका निर्माण कार्य आज तक भी पूरा नहीं हुआ, स्टाफ यहां केवल नाममात्र का है और जो है भी वह ठेकेदारी में है। जिस छोटे से ऑक्सीजन प्लांट को चलाने पर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, उसकी क्षमता मात्र ढाई टन प्रतिदिन की है यानी केवल 20 मरीजो के लिए। इससे भी बड़ी बात तो यह है कि इस प्लांट की स्वीकृति अप्रैल 2020 में हो गयी थी, लेकिन यहां तो आदत आग लगने के बाद कुआं खोदने की है। आज जब तमाम बड़े अधिकारी इस प्लांट को देखने पहुंचे तो क्षेत्र की विधायक सीमा को भी इसे देखने की फुर्सत मिल गयी।

सैक्टर-3 बल्लभगढ़ व सैक्टर-30 में बीते 25 साल से दो-दो एकड़ में बने दुमंजिला अस्पतालों में क्या हो रहा है, जिला प्रशासन जरा वहां भी तो नजर मार लें, सैक्टर-55 में पूर्व मंत्री स्वर्गीय शिवचरण शर्मा ने एक अस्पताल का निर्माण कराया था उसमें आज क्या चल रहा है। बताते हैं वहां 'स्किल यूनिवर्सिटी' का कार्यालय चल रहा है, जबकि स्किल और यूनिवर्सिटी का कोई अता-पता नहीं। इसी सप्ताह सेक्टर 14 के नशा मुक्ति केन्द्र में 50 बेड का इन्तजाम करने की घोषणा की गयी है तो उक्त स्थानों पर तो कम से कम 100-100 बेडों के कोविड वार्ड बनाये ही जा सकते हैं। परन्तु सवाल बड़ा यह है कि नीयत किसकी है काम करने की ? अफसरान मजबूर हैं, जैसे राग अलापने के आदेश खट्टर सरकार देती है, तमाम अफसरान वही राग अलापने लगते हैं। गौरतलब है कि बीते वर्ष के कोविड अनुभव के बावजूद सरकार ने आज तक भी रिक्त पदों को भरने के लिए कोई आवेदन नहीं मांगे हैं। दरअसल सरकार की सोच है कि दो-तीन माह की तो बात है, उसके बाद सब अपने आप ठीक हो जायेगा और यह समय घोषणायें व ड्रामेबाजी करके बिता दिया जाये।

सेक्टर 8 का ईएसआई अस्पताल

करीब 40 वर्ष पहले बनी 200 बेड अस्पताल की इमारत में बमुश्किल 10-15 मरीज ही कभी कभार दाखिल रहते हैं। इस अस्पताल को चलाने का पूरा जिम्मा हरियाणा सरकार के पास है जबकि खर्च का 88½% पैसा ईएसआई कार्पोरेशन देती है। हरियाणा सरकार ने इस अस्पताल की ऐसी दुर्गति कर छोड़ी है कि न तो यहां पर्याप्त डाक्टर हैं न स्टाफ और न ही उपकरण न दवायें। ऑप्रेशन थियेटर तक को बरसों से ताला लगा पड़ा है और तो और रेबिज के इंजेक्शन तक बीते ढाई साल से नहीं है।

जिला प्रशासन जो कूद-कूद कर ईएसआई के मेडिकल कॉलेज अस्पताल की छाती पर जा चढ़ता है वह इस अस्पताल में क्यों नहीं 200 बेड लगवाता? दरअसल यह सरकार चलती गाड़ी की सवारी करना जानती है, खुद कुछ नहीं करना, जो हो रहा है उस पर अपना सेहरा बांध लो।

अटल मेडिकल कॉलेज : फिलहाल कोई आसार नहीं

छायंसा क्षेत्र के गांव मोठूका स्थित इस मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बारे पिछले दो अंकों में काफी विस्तार से लिखा जा चुका है। मुख्यमंत्री खट्टर जो राज्य के देहातों में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, इस अस्पताल के बहाने 26 अप्रैल को मोठूका गांव में पहुंच कर तथा दो दिन में अस्पताल चालू करने की घोषणा करके धन्य हो गये। लेकिन इसके लिये भी पुलिस को खाली मशक्कत करनी पड़ी थी क्योंकि वहां धरने पर बैठे लोगों ने सरकार विरोधी काफी नारेबाजी की थी।

बहरहाल दो दिन में अस्पताल चालू कराने, वह भी फौज के द्वारा, की घोषणा के बावजूद अभी तक वहां सफाई व झाड़ू-पोचे तक का काम नहीं हो पाया है। फौजी अफसर चक्कर तो लगा रहे हैं परन्तु अभी तक कुछ भी किया धरा नजर नहीं आ रहा है। जानकार बताते हैं कि फौजी अफसरों ने सरकार को स्पष्ट कह दिया है कि उनके काम में यहां कोई मंत्री सांसद, विधायक आदि दखल देने न आये। उधर चर्चा है कि सांसद एवं विधायक नौकरी लगवाने के लिये अपनी-अपनी लिस्टें लिये घूम रहे हैं।

मजूदर मोर्चा संवाददाता चन्द्र प्रकाश ने पूरे अस्पताल के भीतर घूमकर 6 मई को फोटो खींचे तथा वीडियो भी बनाया। उन्होंने पाया कि अभी तक अस्पताल पूरी तरह अस्त व्यस्त है। न तो बेड लगे हैं, न कहीं कोई कुर्सी, मेज या स्टूल हैं। बाथरूम सड़े-

पड़े हैं। व्हील चेयर बदहाल स्थिति में पड़ी है। दवा स्टोर एकदम खाली है। लेबोरेट्री का तो ताला ही अभी तक नहीं खुला है, वैसे उसमें बचा हुआ भी कुछ नहीं है। ऑपरेशन थियेटर पूरी तरह से अस्त-व्यस्त है। अस्पताल के डायरेक्टर डा. पवन गोयल से जब संवादाता ने कुछ जानकारी चाही तो पल्ला झाड़ते हुए उन्होंने कहा कि डीसी से बात करो। कितना अजीब जवाब है डायरेक्टर का। दरअसल डायरेक्टर भी क्या करे, बताने लायक कुछ हो तो बताये, जब है ही कुछ नहीं तो डीसी के नाम पर टाल देना ही बेहतर होता है।

गौरतलब बात यह है कि खबर लिखे जाने तक खट्टर सरकार ने इस अस्पताल के लिये न तो कोई पोस्टें सैक्शन की हैं और न हीं किसी तरह के साजो सामान की खरीद के आदेश जारी किये हैं। इसी से स्पष्ट होता है कि सरकार की मंशा सिर्फ प्रोपेगंडा और घोषणाबाजी तक सीमित है। सरकार यह मानकर चल रही है कि महीने, दो महीने में मरने वाले मर लेंगे, बचने वाले बच जायेंगे और लहर समाप्त हो जायेगी फिर उसके बाद बात आई-गई हो जायेगी। इसलिये काम करने का शोर तो जरूर मचाया जाता रहेगा परन्तु काम कोई नहीं करना।

खट्टर की इस चिर-परिचित नौटंकी से परिचित लोग उनकी बात का कोई विश्वास नहीं करते। इसी बात को ध्यान में रखते हुये, अपनी नौटंकी को सच्चा साबित करने के लिये अनेकों वरिष्ठ आईएएस अफसरों को जिलों में तैनात किया है। इन अफसरों को कहा गया है कि वह कोविड मरीजों के लिए बेहतरीन प्रबंधन करें। अब सवाल यह उठता है कि ये उच्चाधिकारी भले ही कितने ईमानदार, सक्षम व कर्मठ हो। खड़े पैर क्या कर सकते हैं। न तो यह कोई नया अस्पताल बना सकते और न ही किसी अस्पताल में बेड बढ़ा सकते और न ही 50 प्रतिशत रिक्त पड़े पदो को यकायक भर सकते हैं। यह अधिकारी केवल दाएं-बाएं भागदौड़ करके मीटिंगे करके चलते हुये अस्पतालों का निरीक्षण करके थोड़ा बहुत सुधार करा सकते हैं। जोकि अपने आप में पर्याप्त नहीं हो सकता। हां, जनता को यह जरूर लगेगा कि खट्टर साहब को वाकई ही जनता की बहुत फ्रिक है इसलिए उन्होंने चण्डीगढ़ में बैठे बड़े अफसरों को जिलों में भेजा है।

रेमडिसिवर और ऑक्सीजन माफिया...

पेज एक का शेष

बेचने के लिए फ़ेसबुक का सहारा

फ़रीदाबाद का ड्रग माफिया रेमडिसिवर बेचने के लिए फ़ेसबुक का भी सहारा ले रहा है। ऐसा ही एक मामला ग्रेटर फ़रीदाबाद में सामने आया है। 3 मई की आधी रात को अतुल यादव और वीरेंद्र बहादुर यादव को सेक्टर 76 में गोल्डन गेट के पास पांच रेमडिसिवर के साथ पकड़ा गया। इन्होंने फ़ेसबुक पर रेमडिसिवर इंजेक्शन का ऑफ़र दिया था। पुलिस और फ़रीदाबाद जिला प्रशासन जो ऐसे लोगों पर नज़र रख रहा है, उसने इनकी गिरफ़्तारी के लिए जाल बिछाया था। आरोपी अतुल यादव ने फ़ोन पर एक रेमडिसिवर इंजेक्शन के 35, 000 रूपये माँगे थे।

हालाँकि एक इंजेक्शन बांग्लादेश में बना हुआ बरामद हुआ है। समझा जाता है कि यह नक़ली है। आरोपियों के खिलाफ़ बीपीटीपी पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया है।

सरगना कौन

पुलिस अभी तक उस असली सरग़ना के पास नहीं पहुँच सकी है जो रेमडिसिवर और अन्य जीवनरक्षक दवाओं की कालाबाज़ारी कर रहा है। ये धंधा बिना मेडिकल स्टोर संचालकों के चलाया नहीं जा सकता। कई मेडिकल स्टोर मालिक सत्तारूढ़ पार्टी में विभिन्न पदाधिकारी हैं। वे अपने नेता के स्वागत में आए दिन होर्डिंग लगाते रहते हैं।

पिछले दस साल से फ़रीदाबाद में क़ब्ज़ा जमाए बैठा ड्रग इंस्पेक्टर करण सिंह गोदारा की जानकारी में सारा धंधा है लेकिन वो कार्रवाई नहीं करता। कुछ मेडिकल स्टोर संचालकों का कहना है कि हम तीन हज़ार रूपये महीना कैश देते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर हमारी जेब में रहता है।

ऑक्सीजन की कालाबाज़ारी मामले को पुलिस ने दबाया

सेक्टर 31 में 3 मई को पत्रकार सौरभ भारद्वाज ने ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाज़ारी को लाइव दिखाया। सेक्टर 31 में क्राइम ब्रांच दफ़्तर के पास एक दुकान में गोदाम बनाकर पचास ऑक्सीजन सिलेंडर जमा किए गए थे। मौक़े से ही सौरभ भारद्वाज ने फ़ोन लगाए लेकिन किसी पुलिस वाले का फ़ोन नहीं उठा। इसके कुछ देर बाद मौक़े पर कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा पहुँच गए। उन्होंने एसएचओ समेत जिले के कई पुलिस अफ़सरों को फ़ोन लगाए लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। विधायक ने डीजीपी मनोज यादव को फ़ोन कर सारी जानकारी दी।

इसके बाद एसएचओ, एसीपी और अन्य पुलिसकर्मी मौक़े पर पहुँचे। एसएचओ ने आते ही कहा कि ये ऑक्सीजन तो दिल्ली के लिए रखी है। जबकि मौक़े पर उस ऑक्सीजन को जमा करने वाला तरूण सेठ नामक व्यक्ति कह रहा है कि मैंने अपने लिया रखा है। एसएचओ ने कहा कि ये तो आफिस है, इनका तातारपुर में काम है। लाइव वीडियो में एसएचओ को पल-पल अलग अलग बयान देते देखा जा सकता है। विधायक नीरज शर्मा ने मौक़े पर केस दर्ज करने की माँग की। तब तक वहाँ बहुत सारे पत्रकार आ गए।

पुलिस ने इस मामले में जो एफआईआर की है, वह अपने आप में हास्यास्पद है। एफआईआर में लॉकडाउन के बावजूद अज्ञात लोगों की भीड़ का हवाला देते हुए कहा है कि इनमें एक शख्स खुद को पत्रकार बता रहा था। लेकिन किसी ने शिकायत नहीं दी और सब एक-एक करके खिसक गए। इस तरह पुलिस ने पत्रकारों को ही लपेटने की कोशिश की।

विधायक नीरज शर्मा ने गुरुवार को अपने बयान में आरोप लगाया कि पुलिस

ने फ़ोन पर उनसे इसकी लिखित शिकायत माँगी। जबकि वह गोदाम पुलिस ने अपने सामने खुलवाया। जहां पचास ऑक्सीजन सिलेंडर रखे थे। विधायक ने कहा कि अगर इस मामले में पत्रकारों पर कोई कार्रवाई हुई तो पुलिस को पहले उन्हें गिरफ़्तार करना होगा। इस बीच पुलिस ने ड्रग इंस्पेक्टर से यह सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया है कि तरूण सेठ नामक शख़्स पचास सिलिंडर अपने पास रख सकता है। इससे साबित हो रहा है कि ऑक्सीजन सिलेंडरों की कालाबाज़ारी को पुलिस ने ड्रग इंस्पेक्टर के साथ मिलकर दबा दिया है। इस सवाल का जवाब मिलना बाक़ी है कि उस गोदाम पर किसी तरह का कोई बोर्ड क्यों नहीं था?

कथित कांग्रेसी गिरफ्तार

रेमडिसिवर और ऑक्सीजन की कालाबाज़ारी में भाजपा नेताओं का नाम उछलने के बाद पुलिस ने गुरूवार को कथित कांग्रेसी नेता विजेन्द्र मावी को ऑक्सीजन सिलेंडरों की कालाबाज़ारी में गिरफ़्तार किया है। खेड़ी पुलिस के मुताबिक़ मावी के घर से 8 भरे हुए ऑक्सीजन सिलेंडर और 32 ख़ाली सिलेंडर बरामद किए गए हैं। पुलिस ने पत्रकारों को बाक़ायदा बुलाकर यह जानकारी दी।

जबकि शहर के सीनियर कांग्रेसी नेताओं ने विजेन्द्र मावी नामक व्यक्ति को पार्टी का पदाधिकारी होने से इनकार किया। वह हमारी पार्टी का स्वयंभू कार्यकर्ता हो सकता है लेकिन इस नाम के व्यक्ति के पास छोटा मोटा पद भी नहीं है।

सरकार ने कराई मेडिकल....

पेज एक का शेष

अपने बयान में आफ़ताब ने कहा कि कोरोना के इलाज के लिए संसाधन मुहैय्या कराने के बजाय पहले के संसाधनों को मेवात से उठवा रही है हरियाणा की बीजेपी जेजेपी सरकार। ऊपर से जायज़ विरोध करने वाले मरीजों के परिजनों व सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ़्तार कर रही है सरकार। मुख्यमंत्री मेवात के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि सोमवार को उन्हीं युवाओं को गिरफ्तार किया जो कोरोना में पिछले 25 दिनों से लगातार लोगों की मदद कर रहे थे। युवाओं के साथ हम खड़े हैं, क्योंकि उनका विरोध जायज़ व स्वाभाविक था और पूरी कानूनी लड़ाई हम लड़ेंगे और मेवात विरोधी बीजेपी जेजेपी सरकार को सबक सिखाने का काम करेंगे।

विधायक आफ़ताब ने मंगलवार को नूंह थाने में जाकर युवकों की गिरफ्तारी का विरोध किया। थाने पर अपना विरोध प्रकट करते हुए आफ़ताब अहमद ने कहा कि सरकार के इस तानाशाही रवैए से इलाक़े के लोग और हम नहीं झुकेंगे। जो कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लड़ी जाएगी। युवाओं की गिरफ्तारी के लिए आदेश बीजेपी जेजेपी सरकार ने ऊपर से दिए थे।